

ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना (Great Green Wall Project)

- अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में **निम्नीकृत भूमि का पुनर्निर्माण** करने तथा विश्व के सर्वाधिक निर्धन क्षेत्र **‘साहेल’** के निवासियों के जीवन-स्तर में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2007 में ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की गई।
- इसके अंतर्गत 11 देशों— **सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती** में लगभग **8000 किमी. ग्रीन वॉल का निर्माण** किया जा रहा है ताकि मरुस्थलीकरण और भूमि-क्षरण को रोका जा सके। निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवंत संरचना होगी।
- इस परियोजना को **अफ्रीकी संघ, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD), विश्व बैंक** तथा **यूरोपीय आयोग** सहित कई भागीदारों के सहयोग से शुरू किया गया था।
- इसके अंतर्गत, वर्ष 2030 तक 100 हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि का पुनर्निर्माण, 250 मिलियन टन कार्बन प्रच्छादन तथा 10 मिलियन हरित रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालाँकि वर्ष 2007 से 20019 तक केवल 4 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि का ही पुनर्निर्माण किया जा सका।
- हाल ही में, फंड की कमी के चलते ग्रीन वॉल का निर्माण कार्य रुक गया था। **निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिये फ्रांस, अफ्रीकी विकास बैंक तथा विश्व बैंक** द्वारा क्रमशः 14, 6.5 तथा 5 बिलियन डॉलर की अनुदान राशि की घोषणा की गई है।



गवि गंगाधरेश्वर मंदिर (Gavi Gangadhareshwara Temple)

- गवि गंगाधरेश्वर अथवा 'गविपुरम गुफा मंदिर' कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में केम्पे गोवडा द्वारा करवाया गया था, जो बेंगलुरु के संस्थापक भी थे। इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है।
- गविपुरम की प्राकृतिक गुफा में बना यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित और अखंड स्तंभों से बना हुआ है। शिव के अलावा यहाँ गणेश, सप्त माता, दो सिर वाले अग्निमूर्ति तथा नाग देवता की प्रतिमाएँ भी स्थापित हैं। इसकी कलात्मकता का उल्लेख वर्ष 1792 में ब्रिटिश चित्रकार जेम्स हंटर के चित्रों में भी मिलता है।
- मंदिर परिसर में लगे ग्रेनाइट के दो स्तंभ आकर्षण का मुख्य केंद्र है, जिन्हें सूरज और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त, यह मंदिर अखंड स्तंभ, डमरू, त्रिशूल तथा विशालकाय आँगन के लिये भी प्रसिद्ध है। यह भारतीय शैलकर्तित (Rock-Cut) स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है।
- यह मंदिर प्रांगण में स्थापित रहस्यमयी स्टोन डिस्क के लिये भी प्रसिद्ध है। इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है कि सूर्य का प्रकाश सीधे मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर ही पड़े। मकर संक्रांति के अवसर पर शाम में यहाँ एक अद्वितीय घटना के दर्शन होते हैं जिसमें सूर्यप्रकाश नंदी के दोनों सींगों के बीच से सीधे गुफा के अंदर स्थापित शिवलिंग पर पड़ता है और संपूर्ण मूर्ति को अद्भुत रोशनी से प्रकाशित कर देता है।
- मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। इस वर्ष बादलों के कारण सूर्य का प्रकाश गुफा में स्थापित शिवलिंग तक नहीं पहुँच सका। विगत 50 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है।



Gavi Gangadhareshwara Temple

19 JANUARY
2 0 2 1

PT CARD



अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, 2020 (Adaptation Gap Report, 2020)

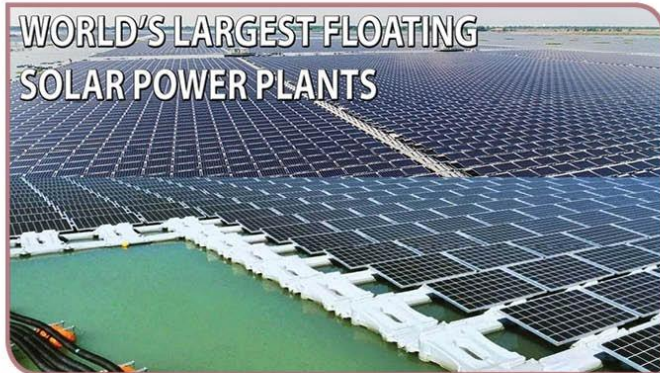
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, 2020 जारी की है। पहली बार यह वर्ष 2014 में जारी की गई थी, तब से प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है।
- यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन हेतु किये जा रहे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संदर्भित करती है। इसके लिये रिपोर्ट में अनुकूलन लागत, अनुकूलन वित्त तथा अनुकूलन वित्त-अंतराल जैसी अवधारणाओं को अपनाया जाता है।
- 'अनुकूलन लागत' में अनुकूलन उपायों की लागत को शामिल किया जाता है, वहीं 'अनुकूलन वित्त' विकासशील देशों के लिये धन प्रवाह को संदर्भित करता है और अनुकूलन लागत तथा अनुकूलन वित्त के बीच का अंतराल 'अनुकूलन वित्त-अंतराल' कहलाता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन प्रभावों के अनुकूलन की वार्षिक लागत वर्ष 2050 तक चौगुनी होने का अनुमान है, अर्थात् वर्तमान में यह लागत 70 बिलियन डॉलर है जो वर्ष 2050 में बढ़कर 280-500 बिलियन डॉलर हो सकती है।
- हालाँकि विकसित देशों की अनुकूलन लागत अधिक है किंतु इनकी जी.डी.पी. के संदर्भ में विकासशील देशों पर अनुकूलन का अधिक दबाव पड़ा है। विकासशील देश विशेषकर अफ्रीकी तथा एशियाई देश, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये कम से कम तैयार हैं, इससे सर्वाधिक प्रभावित होंगे।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के लगभग तीन-चौथाई देशों द्वारा अनुकूलन योजनाएँ अपनाई गई हैं, परंतु इन योजनाओं का कार्यान्वयन तथा वित्तपोषण आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। साथ ही, कोविड-19 महामारी, बढ़ता वैश्विक तापमान, बाढ़, सूखा, दावानल तथा टिड्डियों का प्रकोप जैसी वैश्विक चुनौतियों ने अनुकूलन को प्रभावित किया है। रिपोर्ट में अनुकूलन हेतु प्राकृतिक समाधानों को अपनाने का सुझाव दिया गया है।



5th United Nations
Adaptation Gap Report, 2020

फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट (Floating Solar Project)

- हाल ही में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बाँध पर विश्व की सबसे बड़ी (600 मेगावाट क्षमता) सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किये जाने की घोषणा की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 तक विद्युत उत्पादन शुरू किये जाने की संभावना है, जिससे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति हो सकेगी।



- इस परियोजना के तहत ओंकारेश्वर बाँध के 2000 हेक्टेयर बैकवाटर क्षेत्र में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए जाएँगे। बाँध के जल-स्तर के कम-ज्यादा होने पर, यह पैनल स्वचालित रूप से अपनी स्थिति को ऊपर-नीचे समायोजित करने में सक्षम है। इससे इन पर तीव्र लहरों तथा बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक तथा पावर ग्रिड ने उक्त परियोजना के विकास हेतु सहायता प्रदान करने के लिये सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। साथ ही, विश्व बैंक के सहयोग से परियोजना की प्राथमिक व्यवहार्यता का अध्ययन पूरा किया जा चुका है।
- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) ने केरल में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट (452 KWh क्षमता) का निर्माण किया था। यह परियोजना कंपनी द्वारा 'हरित ऊर्जा पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट' को बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है।



PT CARD



भारतीय नवाचार सूचकांक, 2020 (India Innovation Index, 2020)

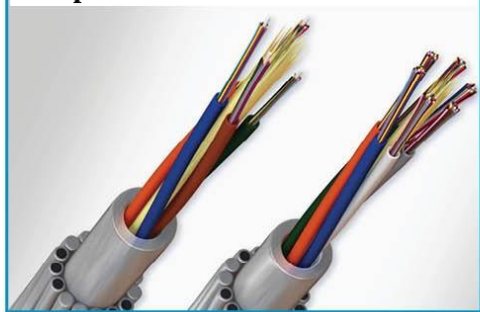
- नीति आयोग ने 'इंस्टीट्यूट फॉर कंपीटिवनेस' के सहयोग से भारतीय नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसका पहला संस्करण अक्तूबर 2019 में जारी किया गया था।
- इस सूचकांक को राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं पर आधारित पाँच कारकों— मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यावसायिक वातावरण, सुरक्षा व कानूनी वातावरण तथा दो प्रदर्शन मापदंडों; ज्ञान उत्पादन व ज्ञान प्रसार के मूल्यांकन के आधार पर जारी किया जाता है।
- इस सूचकांक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है : प्रमुख राज्य (17), पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य (10), केंद्रशासित प्रदेश/सिटी राज्य/छोटे राज्य (09)।
- प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक प्रथम स्थान पर बना हुआ है, जबकि महाराष्ट्र एक स्थान की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान तथा तमिलनाडु एक स्थान नीचे खिसककर तीसरे स्थान पर आ गया है। ध्यातव्य है कि प्रमुख राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष पाँच स्थानों पर चार दक्षिणी राज्य— कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल शामिल हैं। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में सबसे नीचे क्रमशः बिहार (17वीं), छत्तीसगढ़ (16 वीं) और झारखंड (15वीं) का स्थान है।
- पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर, जबकि चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर आ गया है।
- विदित है कि कर्नाटक को वेंचर कैपिटल सौदों, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के निर्यात के कारण प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, राज्य में बढ़ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से भी नवाचार क्षमताओं में वृद्धि हुई है।

India Innovation Index, 2020			
Rank	Major States	Score	
1	Karnataka	42.50	
2	Maharashtra	38.03	
3	Tamil Nadu	37.91	
4	Telangana	33.23	
5	Kerala	30.58	
6	Haryana	25.81	
7	Andhra Pradesh	24.19	
8	Gujarat	23.63	
9	Uttar Pradesh	22.85	
10	Punjab	22.54	
Rank	NE and Hill States	Score	
1	Himachal Pradesh	25.06	
2	Uttarakhand	23.50	
3	Manipur	22.78	
4	Sikkim	20.28	
5	Mizoram	16.93	
Rank	UTs And City States	Score	
1	Delhi	46.60	
2	Chandigarh	38.57	
3	Daman & Diu	26.76	
4	Puducherry	25.23	
5	Goa	24.92	

ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (Optical Ground Wire - OPGW)

- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 500 किमी. ऑप्टिकल ग्राउंड वायर टेलिकॉम नेटवर्क का उपयोग कर पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार को बेहतर बनाने के लिये, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। पावरग्रिड विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। विदित है कि राज्य में पहले से 350 किमी. ओ.पी.जी.डब्ल्यू. का उपयोग किया जा रहा है।
- ऑप्टिकल ग्राउंड वायर एक ट्यूबलर संरचना होती है, जिसमें एक या एक से अधिक ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जो एल्यूमीनियम और स्टील के तार की परतों से घिरे होते हैं। ये टावर को जमीन से जोड़ने का काम करते हैं। आई.ई.ई.ई. (Institute of Electrical and Electronics Engineers) मानक के अनुसार **ऑप्टिकल ग्राउंड वायर को ऑप्टिकल फाइबर कम्पोजिट ओवरहेड ग्राउंड वायर के रूप में भी जाना जाता है।** यह एक प्रकार की केबल है, जिसका उपयोग ओवरहेड पावर लाइनों में ग्राउंडिंग और संचार के कार्यों को जोड़ने में किया जाता है।
- केबल के भीतर ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग उपयोगिताओं के बीच उच्च गति डेटा टेलीमेट्री तथा शहरों के बीच उच्च गति के फाइबर इंटरकनेक्शन हेतु तीसरे पक्ष को बेचने के लिये किया जाता है।
- प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों, भूस्खलन और दुर्गम इलाकों के कारण राज्य को सीमित दूरसंचार नेटवर्क पहुँच का सामना करना पड़ रहा था। इस नेटवर्क के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाता, राज्य में दूरदराज के लोगों को निर्बाध मोबाइल/इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम होंगे।

Optical Ground Wire - OPGW





PT CARD



लघु सीमित देयता भागीदारी (Small Limited Liability Partnership)

- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने लघु और सूक्ष्म उद्यमों के लाभ हेतु 'लघु सीमित देयता भागीदारी' (LLP) के गठन की अनुशंसा की है। इसके लिये एल.एल.पी. अधिनियम की धारा 2 (1) में एक नया खंड (ta) जोड़ा जाएगा।
- लघु उद्यमियों के लिये व्यापार सुगमता के उद्देश्य से इसमें अपेक्षाकृत सीमित अनुपालन तथा कारोबार में योगदान के आधार पर कम शुल्क व आर्थिक जुर्माने के भुगतान का प्रावधान किया गया है। पैनल ने एल.एल.पी. अधिनियम में संशोधन कर 12 अपराधों को अपराधिक श्रेणी से बाहर करने का सुझाव दिया है।
- पैनल ने ऋण बाजार से आसानी से पूंजी जुटाने के लिये एल.एल.पी. को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) जारी करने की अनुमति देने की सिफारिश की है। विदित है कि एल.एल.पी. अधिनियम 2008 एल.एल.पी. को ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने की अनुमति नहीं देता है।
- एल.एल.पी. एक प्रकार की कॉरपोरेट इकाई होती है, जिसमें प्रत्येक भागीदार की देयता उसके द्वारा किये गए निवेश के आधार पर तय होती है। एल.एल.पी. को अनुभवी पेशेवरों के समूह द्वारा बनाया और प्रबंधित किया जाता है।



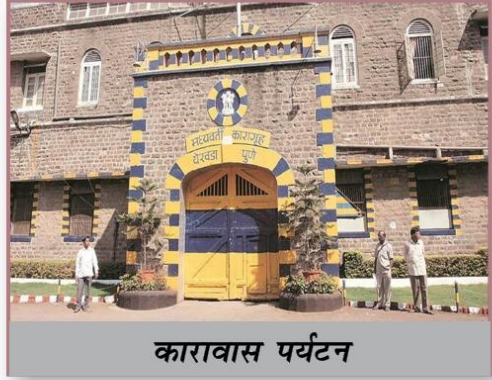
25 JANUARY
2021

PT CARD



कारावास पर्यटन (Jail Tourism)

- महाराष्ट्र सरकार, राज्य के कारावासों के ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हुए 26 जनवरी को **कारावास पर्यटन पहल** शुरू करेगी। इस पहल का पहला चरण पुणे स्थित 150 वर्ष प्राचीन यरवदा जेल से प्रारंभ होगा।
- कई स्वतंत्रता सेनानियों को यरवदा जेल में कैद किये जाने के कारण इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल का दूसरा चरण नागपुर, ठाणे और रत्नागिरी जेलों में शुरू होगा।
- महाराष्ट्र में विभिन्न जेलों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक विशिष्ट महत्त्व है। **महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू** सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया था, को यरवदा जेल में कैद किया गया था।
- अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ समझौता, जिसे **‘पूना पैक्ट’** के नाम से जाना जाता है, यरवदा सेंट्रल जेल में संपन्न हुआ था। महान क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी **चापेकर बंधुओं** ने भी इसी कारावास में देश की आजादी के लिये अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस पहल के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य के जेल विभाग को सौंपी गई है।



कारावास पर्यटन

27 JANUARY
2 0 2 1

PT CARD



प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 3.0)

- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 15 जनवरी, 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण (PMKVY 3.0) का शुभारंभ किया है। विदित है कि कौशल विकास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, जिसके तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- योजना के तीसरे चरण को वैश्विक एवं स्थानीय स्तर पर बदलती कौशल मांगों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है, जो 'वोकल फॉर लोकल' दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके अंतर्गत, लगभग 600 केंद्रों में 300 से अधिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, इसका उद्देश्य कौशल विकास को अधिक मांग-संचालित बनाना और अधिक विकेंद्रीकृत करना है।
- यह योजना दो चरणों में लागू की जाएगी। पहला चरण वर्ष 2020-21 में पायलट आधार पर चलाया जाएगा। इसके तहत 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिये लगभग 200 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। दूसरे चरण (2021-2026) के लिये कार्यान्वयन ढाँचे के निर्माण की शुरुआत कर दी गई है।
- राज्य कौशल विकास मिशन के मार्गदर्शन में जिला कौशल समितियाँ (DSCs) जिला स्तर पर कौशल अंतराल को कम करने तथा आवश्यकताओं का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तीसरा चरण राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर संपर्क को और मजबूत करके परिणाम प्राप्त करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

Features of PMKVY 3.0

- Cross utilisation of existing infrastructure for establishment of skilling centres
- Introduction of significant reforms in the assessment ecosystem
- Creation of a pool of certified trainers through direct funding for the Training of Trainers Program (ToT)

☎ 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें-9555-124-124 🌐 www.sanskritiIAS.com 📺 📱 📧 📞

28 JANUARY
2 0 2 1

PT CARD



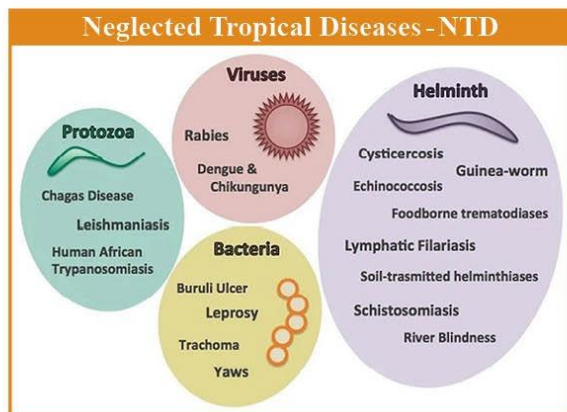
द ग्रेट रीसेट (The Great Reset)

- 'द ग्रेट रीसेट' विश्व आर्थिक मंच (WEF) की एक पहल है। इसकी अवधारणा डब्ल्यू.ई.एफ. के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब द्वारा दी गई है, जो पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई।
- यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के गहरे संकट के आकलन पर आधारित है। समाज पर महामारी के विनाशकारी प्रभाव, उभरती प्रौद्योगिकी के प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन के परिणामों सहित कई अन्य कारकों के कारण वर्तमान में आर्थिक स्थिति अधिक खराब हुई है।
- क्लॉस श्वाब के अनुसार, वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सभी घटकों को पुनर्जीवित करने के लिये शिक्षा, सामाजिक अनुबंध व कार्यशील परिस्थितियों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये। अमेरिका से लेकर चीन तक प्रत्येक देश को तेल व गैस से लेकर तकनीक तक प्रत्येक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिये इसमें सहभागिता करनी चाहिये। संक्षेप में, उन्होंने 'पूँजीवाद के ग्रेट रीसेट' की आवश्यकता पर बल दिया है।
- 'द ग्रेट रीसेट' का एजेंडा पूँजीवादी व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ गहराते जलवायु संकट तथा वैश्विक सहयोग में आई कमी जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके लक्ष्यों में संयुक्त रूप से एवं तात्कालिक प्रभाव की दृष्टि से अधिक निष्पक्ष, धारणीय तथा लचीले भविष्य के लिये आर्थिक व सामाजिक प्रणाली का आधार बनाने की प्रतिबद्धता भी शामिल है।



उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Diseases - NTD)

- 'उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग' (NTD) **उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोगों का एक विविध समूह** है, जो सामान्यतः अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील क्षेत्रों की कम आय वाली आबादी में पाए जाते हैं।
- ये कई प्रकार के रोगजनकों, जैसे- वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवियों (हेल्मिंथ्स) द्वारा संचरित होते हैं। इन रोगों में डेंगू, रेबीज, ब्लाईंड ट्रेकोमा, बुरुली अल्सर, एंडीमिक ट्रेपोनोमेटोसिस (Yaws), कुष्ठ रोग (हैंसेन रोग) आदि प्रमुख हैं। वैश्विक रूप से प्रत्येक 5 में से 1 व्यक्ति एन.टी.डी. रोग से प्रभावित है।
- ध्यातव्य है कि अन्य संक्रामक रोगों जैसे एड्स, तपेदिक और मलेरिया के लिये उपचार व नैदानिक सुविधाएँ व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जबकि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग से ग्रसित रोगियों की संख्या अधिक होने के बावजूद इनसे जुड़ी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है।
- रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार आवश्यक एवं प्रभावी नैदानिक उपायों के माध्यम से 6 प्रमुख एन.टी.डी. रोगों- गिनीकृमि (Dracunculiasis), लसीका फाइलेरिया, ओंकोकोर्सियासिस (Onchocerciasis), शिस्टोसोमियासिस (Schistosomiasis), मृदा संक्रमित हेल्मिंथ्स (एस्केरिस, हुकवर्म और व्हिपवर्म) तथा ट्रेकोमा को नियंत्रित या पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है।
- विदित है कि 30 जनवरी, 2021 को द्वितीय वार्षिक 'विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस' मनाया जाएगा, जो ऐसे रोगों को समाप्त करने के लिये वैश्विक समुदाय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



बुनियादी आवश्यकता सूचकांक (Bare Necessities Index - BNI)

- देश में समानता का आकलन करने के उद्देश्य से आर्थिक समीक्षा 2020-21 में ग्रामीण, शहरी तथा विभिन्न आय-समूहों के परिवार के प्रत्येक सदस्य तक बुनियादी आवश्यकताओं की पहुँच सुनिश्चित करने और इसके महत्त्व को ध्यान में रखते हुए 'बुनियादी आवश्यकता सूचकांक' की रूपरेखा तैयार की गई है।
- बी.एन.आई. को 5 आयामों— जल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य मूलभूत सुविधाओं तक पहुँच में हुई प्रगति तथा 26 संकेतकों के मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है। यह सूचकांक आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में उपयोग किये गए 'थालीनॉमिक्स' के विचार पर ध्यान देता है। 'थालीनॉमिक्स' के माध्यम से देश में भोजन तक पहुँच की जाँच करने की माँग की गई थी।
- सूचकांक मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुँच के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को उच्च, मध्यम तथा निम्न तीन स्तरों में वर्गीकृत करता है। उच्च स्तर राज्य में बुनियादी आवश्यकताओं की बेहतर पहुँच का संकेत देता है। इसे एन.एस.ओ. से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग करते हुए वर्ष 2012 और 2018 हेतु तैयार किया गया है।
- विभिन्न योजनाएँ, जैसे— जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि गरीबी निवारण, पेयजल, स्वच्छता व आवास तक पहुँच में अंतराल को कम कर वर्ष 2030 तक एस.डी.जी. लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उपयुक्त रणनीति तैयार करने में सहायक हो सकती हैं।
- वर्ष 2018 में केरल, पंजाब, हरियाणा तथा गुजरात में आधारभूत आवश्यकताओं तक सर्वाधिक पहुँच थी, जबकि इस संदर्भ में ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा सबसे निचले स्थानों पर रहे।

IMPROVING QUALITY OF LIFE

Improvement in the Bare Necessities Across India
(Rural + Urban) from 2012 to 18

